भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 3723
मंगलवार, 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

इथेनॉल उत्पादन हेतु सहकारी समितियाँ

†3723. श्री राजेश वर्माः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्रीमती शांभवीः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इथेनॉल उत्पादन हेतु सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने हेतु तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा की गई पहल की नीतिगत रूपरेखा और सहकारी समितियों के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और किसानों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की उम्मीद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, ऊर्जा सुरक्षा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी पर इस पहल का अनुमानित प्रभाव क्या है; और
(घ) सहकारी समितियों को उनकी इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता के लिए क्या उपाय किए गए हैं, जिनमें वित्तीय सहायता, अवसंरचना विकास और तकनीकी सहायता शामिल है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): चीनी उद्योग भारत के सबसे बड़े कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों में से एक है। इस उद्योग से 5 करोड़ गन्ना किसान और उनके आश्रित जुड़े हुए हैं। चीनी ने अपने मूल्यवर्धन चरित्र से स्वयं को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास का एक बहुत शक्तिशाली साधन बना लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यह उद्योग किसानों और संबंधित ग्रामीण आबादी के आर्थिक कल्याण से निकटता से जुड़ा हुआ है।

देश भर में 229 कार्यशील सहकारी चीनी मिलें हैं (स्रोत: एनसीडी पोर्टल)। वे सामूहिक रूप से भारत में उत्पादित कुल चीनी का लगभग 30% योगदान करते हैं। हालांकि, सहकारी चीनी मिलों(CSMs) को विभिन्न वित्तीय मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा सावधि ऋणों और कार्यशील पूंजी ऋणों की सर्विसिंग शामिल थी। अतः उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि वे इथेनॉल के उत्पादन से अतिरिक्त राजस्व सृजित करें, जिससे उनकी लाभप्रदता बढ़ेगी।

जैव ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति - 2018, तथा 2022 में यथासंशोधित, अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल (EBP-20) में इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य 2030 से इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 तक बढ़ा दिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को 1120 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी।

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को इथेनॉल की आपूर्ति के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों(CSMs) को EBP-20 में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने "सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अनुदान सहायता" नामक योजना शुरू की है । इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी को वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक में 500.00 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 1000.00 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया गया था, जिसका उद्देश्य इथेनॉल संयंत्र/कोजेनरेशन संयंत्र की स्थापना के लिए सहकारी चीनी मिलों(CSMs) को 10,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने और उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता या तीनों को पूरा करने के लिए बाजार से अतिरिक्त निधि उधार लेना था।

जबकि उपरोक्त योजना का उद्देश्य सहकारी चीनी मिलों(CSMs) द्वारा नए इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्चे माल अर्थात शीरे और चीनी के सिरप की उपलब्धता कई कारकों से सीमित है, जैसे कि गन्ने के सिरप के परिवर्तन पर सरकारी नीति, इथेनॉल के उत्पादन के लिए भारी शीरा और गन्ना पेराई के मौसम की अवधि और वर्षा आदि पर निर्भर गन्ने की उपलब्धता पर आधारित है । सीमित कारकों के कारण, इथेनॉल संयंत्रों वाली सहकारी चीनी मिलें(CSMs) अपनी पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम नहीं हैं।

इन चुनौतियों को दूर करने और डिस्टिलरी का साल भर संचालन सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने मौजूदा शीरा आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए एक पहल की है। शीरा आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों में बदलने से मौसमी गन्ना-आधारित फीडस्टॉक्स पर क्षेत्र की निर्भरता कम हो जाएगी और अनाज, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और कृषि अवशेषों जैसे वैकल्पिक कच्चे माल का उपयोग करने में अधिक लचीलापन मिलेगा।

इथेनॉल डिस्टिलरी वाली सहकारी चीनी मिलों(CSMs) को मल्टी-फीड इथेनॉल डिस्टिलरी में बदलने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:

(i) एनसीडीसी 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसमें समिति को परियोजना लागत का केवल 10% और परियोजना लागत का 90% एनसीडीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन होगा।

(ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) अपनी मौजूदा गन्ना-आधारित इथेनॉल इकाइयों को मल्टी-फीडस्टॉक-आधारित इथेनॉल इकाइयों (मक्का और चावल जैसे अनाज का उपयोग करते हुए) में परिवर्तित करने के लिए सहकारी चीनी मिलों(CSMs) को ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक योजना लागू कर रहा है।

(iii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की उपर्युक्त योजना के तहत ब्याज अनुदान का लाभ उठाने वाली सहकारी चीनी मिलों को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा पहली प्राथमिकता दी जाएगी ताकि एकल-फीड इथेनॉल संयंत्रों से बहु-फीड इथेनॉल संयंत्रों में उनके संक्रमण की सुविधा मिल सके।

उपरोक्त पहल न केवल एक स्वच्छ ईंधन मिश्रण और कार्बन उत्सर्जन में कमी में योगदान देगी, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात प्रतिस्थापन का भी समर्थन करेगी, जिससे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में सुधार होगा। इसके अलावा, यह सहकारी चीनी मिलों की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाकर और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त करता है।

*****